

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्र-परिषद के नरिणय

चर्चा में क्यों?

16 मई, 2023 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्र-परिषद की बैठक में अनुसूचित जाति के वदियार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लिये गए।

प्रमुख बदि

- मंत्र-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा के परपालन में अनुसूचित जाति के वदियार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये वार्षिक आय सीमा में वृद्धि की है। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के वदियार्थियों को शक्ति प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- मंत्र-परिषद ने मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना-2023 के 3 वर्षीय बजट एवं वत्तीय प्रावधानों के (वत्तीय वर्ष 2023-24 से वत्तीय वर्ष 2025-26 तक) अंतरगत 41 हजार 923 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की।
- मंत्र-परिषद ने शासन संधारति मंदरिों की कृषि भूमियों के प्रबंधन के संबंध में 22 अप्रैल, 2023 को जारी वभागीय आदेश का अनुसमर्थन कयि।
 - आदेश अनुसार जनि शासन संधारति मंदरिों के पास 10 एकड़ तक कृषि भूमि संलग्न है, उनसे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे।
 - शेष कृषि भूमियों को ज़िला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपना कर कृषि प्रयोजन के लिये नीलामी कर सकेंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली आय मंदरि के खाते में जमा कराई जाएगी।
- मंत्र-परिषद द्वारा प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत वर्ष 2023-24 के लिये अग्रमि भंडारण एक फरवरी से 31 मई की अवधि में 10 लाख 80 हजार टन मात्रा कयि जाने का नरिणय लयि गया।
 - उल्लेखनीय है कि रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्स एवं पोटाश) की अग्रमि भंडारण योजना में राज्य में डीएपी, कॉम्प्लेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी वपिणन संघ को राज्य नोडल एजेंसी घोषित कयि गया है।
- मंत्र-परिषद द्वारा केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कंप्यूटराईजेशन के लिये केंद्र प्रायोजित परियोजना में प्रदेश की 4534 पैक्स का कंप्यूटराईजेशन कराए जाने की स्वीकृति दी गई।
 - वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वभाग द्वारा भारतनेट योजना अनुसार प्रदेश की 4534 पैक्स के मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- मंत्र-परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा समेकित बाल-संरक्षण योजना 'मशिन वात्सल्य' को नवीन नार्म्स अनुसार प्रदेश के सभी ज़िलों में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्र-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नयिम-2019 में संशोधन का अनुमोदन कयि गया।
 - प्रदेश में 44 ज़िलों के रेत समूहों का 'ई-नविदि' के स्थान पर 'ई-नविदि-सह-नीलामी' प्रक्रिया द्वारा समूहवार ठेके से नरिवर्तन कयि जाएगा।
 - ठेके की अवधि, अनुबंध दनिंक से 3 वर्ष (दो अतिरिक्त वर्ष हेतु वसितारणीय) नरिधारित कयि जाएंगे।
 - राज्य खनजि नगिम द्वारा वैधानिक अनुमतियाँ (माइनिंग प्लान/पर्यावरण अनुमति/जलवायु सममति आदि) प्राप्त की जाएंगी।
 - नविदि में सफल एम.डी.ओ. (माईस डेवलपर कम ऑपरेटर), कलेक्टर एवं नगिम के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध का नषिपादन कयि जाएगा।
 - ठेका राशा की देयता त्रैमासिक के स्थान पर मासिक कश्ति के रूप में और ठेका राशा में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष जुलाई के स्थान पर ठेका संचालन का 1 वर्ष पूरण होने पर की जाएगी।